नईदुनिया

सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, अरबों डॉलर बढ़ गया है खजाना

नई दिल्ली ।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार पांचवे सप्ताह शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। 22 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 642.631 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। यह अब तक का सर्वोच्च स्तर है।

आरबीआई रिपोर्ट की खास बातें

पांचवे सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा कोष में 140 मिलियन डॉलर की वृद्धि देखने को मिली है। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई। इससे पहले विदेशी मुद्रा भंडार का सर्वोच्च स्तर 2021 में देखा गया था। उस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 642.453 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था।

भारत के गोल्ड रिजर्व में जबरदस्त बढ़ोतरी

आरबीआई का कहना है कि 22 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान सोने का भंडार 347 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा है। इस बढ़त के बाद भारत को गोल्ड रिजर्व 51.487 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। आरबीआई को कहना है कि इस दौरान एसडीआर यानी विशेष आहरण अधिकार घटा है। भारत का एसडीआर 57 मिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 18.219 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि समीक्षाधीन सप्ताह में आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति भी 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर कम होकर 4.662 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 22 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौन विदेशी मुद्रा संपत्ति 123 मिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 568.264 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है।

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पीएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार

नई दिल्ली । ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए सदस्यों की पहचान अब्दुल खादर पुत्तूर, अंशद बदरुद्दीन और फिरोज के तौर पर की गई है। गिरफ्तार किए गए सदस्यों को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। एजेंसी ने तीनों लोगों पर पीएफआई कैडर को हथियार प्रशिक्षण देने और इस प्रतिबंधित संगठन से पर्याप्त धन प्राप्त करने का आरोप लगाया है। 2022 में केंद्र ने पीएफआई के आतंकवादी गतिविधियों के साथ संबंध को लेकर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित कर दिया था।

न्यूज ब्रीफ

आईपीओ से 70,000 करोड़ जुटा सकती हैं कंपनियां, 2024-25 में शेयर बाजारों में तेज उछाल का मिलेगा फायदा

नई दिल्ली। कंपनियां 2024-25 में प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से 70,000 करोड़ रुपये जुटा सकती हैं।2023-24 में कंपनियों ने आईपीओ से 62,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। शेयर बाजार की तेजी अगले वित्त वर्ष में भी जारी रहने की उम्मीद है। इसलिए, इसका फायदा इश्यू लाने वाली कंपनियां उठा सकती हैं। विदेशी निवेशक भी बाजार में अच्छी खासी रकम निवेश कर सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार, 19 कंपनियां मिलकर 25,000 करोड़ रुपये जुटा सकती हैं। इन सबको पूंजी बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। 37 कंपनियां इश्यू से 45,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही हैं। इन्होने सेबी के पास मसौदा जमा कराया है। सभी कंपनियां सेबी से मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। कुल 56 कंपनियों में से नौ कंपनियां नए जमाने की टेक सेक्टर की हैं। ये करीब 21,000 करोड़ रुपये आईपीओ के जरिये जुटा सकती हैं। अगले वित्त वर्ष में आईपीओ की रफ्तार तेज रहने की उम्मीद है। बड़ी कंपनियां भी बाजार में उतरने वाली हैं। इसमें टाटा कैपिटल से लेकर बिग बॉस्केट तक शामिल हैं। आईपीओ को जिस वजह से तेजी मिलेगी, उनमें घरेलू पूंजी में वृद्धि, बेहतर गवर्नेंस, एफडीआई समर्थन के साथ अनुकूल सरकारी नीतियां और संस्थागत निवेशक शामिल हैं। विशेषज्ञों की मानें तो आम चुनाव के बावजूद अप्रैल व मई में कुछ आईपीओ लॉन्च होते दिखेंगे। टाटा समूह अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी को बाजार में लिस्ट कराने की योजना बना रहा है। हालांकि, अभी तक रकम का खुलासा नहीं हुआ है। स्विगी भी बाजार में उतरने वाली है।

गरीबों-वंचितों के खिलाफ है कांग्रेस', डिमांड नोटिस को लेकर सीएम सरमा का विपक्ष पर कटाक्ष

दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने आयकर विभाग के नोटिस को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है। सरमा ने कहा है कि अगर पार्टी द्वारा अपने टैक्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि यह पार्टी गरीबों और वंचितों के खिलाफ है। कांग्रेस के सबसे कड़े आलोचकों में से एक सरमा ने कहा है यह पार्टी गरीबों को लाभ देने से इनकार कर रही है। बता दें कि आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है। यह डिमांड नोटिस आकलन वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए जारी किया गया है, जिसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि इसका मतलब यह है कि कांग्रेस कल्याणकारी गतिविधियों के खिलाफ है। यह पार्टी गरीबों और वंचितों के खिलाफ है। उधर इस मामले में विपक्ष ने सत्तारूढ़ भाजपा पर कर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला प्रीपेड रिश्वत रूट, पोस्टपेड रिश्वत रूट, पोस्ट-रेड ग्रुप, और शेल कंपनियों के माध्यम से किया गया था। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि यह 'टैक्स टेररिज्म' है और इसका इस्तेमाल कांग्रेस पर हमला करने के लिए किया जा रहा है।

2024-25 में घटकर 2.1 फीसदी रह जाएगा बैंकों का कुल एनपीए, 2.5-2.7 फीसदी रह सकता है जीएनपीए

मुंबई। घरेलू बैंकों के सकल बुरे फंसे कर्ज (जीएनपीए) 2024-25 के अंत तक घटकर 2.1 फीसदी पर आ सकते हैं। 2023-24 में बैंकिंग प्रणाली का जीएनपीए 2.5-2.7 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है। घरेलू रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने कहा, 2015-16 की एक्यूआर प्रक्रिया के कारण जीएनपीए 2013-14 के 3.8 फीसदी से बढ़कर 2017-18 में 11.2 फीसदी पहुंच गया। इसने बैंकों को एनपीए की पहचान करने और गैर-जरूरी पुनर्गठन को कम करने के लिए प्रेरित किया। रिपोर्ट के मुताबिक, जीएनपीए में 2018-19 से सुधार देखा जा रहा है। 2022-23 में यह सुधरकर एक दशक के निचले स्तर 3.9 फीसदी पर आ गया। 2023-24 की दिसंबर तिमाही में जीएनपीए तीन फीसदी था। एजेंसी ने कहा, वसूली और खराब कर्ज को बट्टे खाते में डालने से संपत्ति की गुणवत्ता सुधरी है।

1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचेगा निर्यात, नये बाजारों में 2030 तक बढ़ेगी भारतीय उत्पादों की मांग

नई दिल्ली ।
दुनियाभर में व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं के बावजूद भारत से निर्यात तेजी से नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। द्विपक्षीय करार, मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका व मध्य एशिया जैसे नए बाजारों तक पहुंच से भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात 2030 तक बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन नई पहलों के साथ भारत से कीमती धातुओं, खनिजों, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक रसायन, कपड़ा, मसालों और रक्षा उपकरणों के निर्यात में आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई है। इससे भारत से निर्यात फरवरी, 2024 में सालाना आधार पर 11.9 फीसदी बढ़कर 41.4 अरब डॉलर पहुंच गया। यह मार्च, 2023 के बाद सर्वाधिक निर्यात है। इसके अलावा, भारत ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य एशिया जैसे नए बाजारों में अप्रैल-दिसंबर, 2023 अवधि के दौरान 23.4 करोड़ डॉलर की कारों, दोपहिया-तिपहिया वाहनों व कीमती धातुओं समेत अन्य उत्पादों का निर्यात किया।

बेहतर संभावनाओं के बीच लक्ष्य पाना संभव

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, मध्य से लंबी अवधि में भारतीय निर्यात को लेकर संभावनाएं काफी उत्साहजनक हैं। हम 2030 तक एक-एक लाख करोड़ डॉलर की वस्तुओं व सेवाओं दोनों के निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में अग्रसर हैं।

हालांकि, 2024-25 की पहली तिमाही में उच्च महंगाई व विभिन्न देशों के बीच तनाव से निर्यात के मोर्चे पर भारत को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सहाय ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी फेड रिजर्व अपनी अगली समीक्षा में दरों में कटौती करना शुरू कर देगा। इससे अन्य देश के केंद्रीय बैंक भी दरें घटाने को प्रेरित होंगे, जिससे मांग को बढ़ावा मिलेगा।

लाल सागर संकट को भारत ने बनाया अवसर

फियो महानिदेशक ने कहा, हम बहुत ही कम अवधि

में संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साझेदार देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि देख रहे हैं। इन देशों में निर्यात में बहुत तेज वृद्धि हो रही है। मौजूदा लाल सागर संकट पर उन्होंने कहा, यह वैश्विक व्यापार के लिए एक नई चुनौती है। लेकिन, भारत ने चतुराई से इस विपरीत स्थिति को अवसर में बदल दिया है। केप ऑफ गुड होप के जरिये लंबे मार्गों को अपनाने से अफ्रीका-अमेरिका में नए बाजार खुल रहे हैं।

बंद हो रहा 'न्यूज' टैब फीचर, फेसबुक पर समाचारों के लिए नहीं दिखेगी फीड

लॉस एंजलिस। फेसबुक का 'न्यूज' टैब जल्द ही बंद हो जाएगा। यानी अब फेसबुक पर समाचारों के लिए अलग से कोई टैब या फीड नहीं होगा। कंपनी ने कहा कि वह अप्रैल से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में न्यूज टैब बंद कर देगी और समाचारों के लिए कोई नया व्यापारिक समझौता नहीं करेगी। साथ ही कंपनी ने कहा कि वह भविष्य में समाचार प्रकाशकों के लिए कोई विशेष प्रोडक्ट नहीं लाएगी। अब कंपनी का विचार समाचारों पर कम जोर देने का है। यह सुविधा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में पिछले साल बंद कर दी गई थी। 'फेसबुक न्यूज' टैब की शुरुआत 2019 में की गई थी। और इसमें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय को जारी किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फेसबुक को इस प्रयोग से भारी उम्मीदें थीं, लेकिन लोग समाचार पढ़ने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। फेसबुक पर केवल तीन प्रतिशत ही समाचार होता है। फिलहाल फेसबुक शॉर्ट वीडियो समेत उस सामग्री पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसे लोग देखना चाहते हैं।

नई बीमा पॉलिसी एक अप्रैल से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होंगी जारी

नई दिल्ली ।
अगर आप 1 अप्रैल 2024 के बाद बीमा खरीदने वाले हैं, तो अब यह आपको सिर्फ डिजटल फॉर्मेट में ही मिलेगा। क्योंकि अब बीमा कंपनी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण नियमों के अनुसार पॉलिसी सिर्फ डिजिटल रूप में जारी करेगी। नए नियमों के मुताबिक, बीमा कंपनियों के लिए डीमैट फॉर्म में पॉलिसी जारी करना अनिवार्य है और अब इसे चार बीमा रिपोजिटरी - सीएएमएस रिपोजिटरी, (कार्वी), डेटाबेस मैनेजमेंट और सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑफ इंडिया द्वारा सुगम बनाया जाएगा।

ई-बीमा खाते क्या हैं -ई-बीमा खातों में डिजिटल रूप में पॉलिसी जारी करना और रखना शामिल है। जबकि ज्यादातर निजी बीमाकर्ता पहले से ही पॉलिसीधारकों के लिए ई-बीमा खाते खोलते हैं, पॉलिसीधारक अन्य पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने और रखने का ऑप्शन चुन सकते हैं।

अब क्या बदल जाएगा- 1 अप्रैल से बीमा कंपनियों के लिए सिर्फ डिजिटल पॉलिसी जारी करना अनिवार्य है। नियमों में कहा गया है, चाहे प्रपोजल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिला हो या किसी और तरीके से, हर बीमाकर्ता सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप में बीमा पॉलिसी जारी करेगा।

अगर आप अपनी पॉलिसी को भौतिक रूप में रखना चाहते हैं तो **क्या होगा** - यह विकल्प अभी भी उपलब्ध है और आप पुरानी पॉलिसी को भौतिक रूप में रखना जारी रख सकते हैं। बीमा खरीदने के लिए प्रस्ताव फॉर्म भरते समय आप भौतिक प्रति पर भी जोर दे सकते हैं।

ई-बीमा खाता कैसे खोलें- नई पॉलिसी खरीदते समय ई-बीमा खाता खोला जा सकता है। आप मौजूदा, भौतिक बीमा पॉलिसी को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदल सकते हैं।

जोखिम खत्म होगा-विशेषज्ञों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से पॉलिसी धारकों को काफी फायदा पहुंचेगा। यह पहल न केवल सुविधा प्रदान करती है, बल्कि पॉलिसीधारक पोर्टफोलियो की सुरक्षा और प्रबंधन को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। पॉलिसी होल्डर को कागजी दस्तावेज खोने, फटने का डर रहता हैं लेकिन अब यह जोखिम नही होगा।

यह होंगे फायदे

1. एक स्थान पर ही सभी बीमा पॉलिसी देख सकेंगे, डाउनलोड कर पाएंगे
2. कागजी दस्तावेजों की डिजिटल प्रारूप के खोने का जोखिम कम होगा
3. ई-बीमा खाते में एक साथ सभी बीमा पॉलिसी को अपडेट कर पाएंगे
4. पॉलिसी विवरण और नवीनीकरण तिथियों को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे

सरकार ने 20 में से 13 मिनेरल ब्लॉक की नीलामी रद्द की, निराशाजनक प्रतिक्रिया बनी कारण

नई दिल्ली ।
महत्वपूर्ण खनिजों की पहली किश्त में बिक्री के लिए रखे गए 20 ब्लॉकों में से 13 की नीलामी सरकार ने रद्द कर दी है। खान मंत्रालय के मुताबिक निराशाजनक प्रतिक्रिया की वजह से यह फैसला लिया गया।

दो ब्लॉकों के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी

खान मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा, 13 मार्च 2024 की अधिसूचना के जरिए 13 खनिज ब्लॉकों के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था, जिसमें दो ब्लॉकों के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी और 11 ब्लॉकों के लिए तीन से कम तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता (टीक्यूबी) थे।

सात खदानों को तीसरे दौर में नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया

प्रस्ताव पर रखे गए 20 ब्लॉकों में से 18 ब्लॉकों के लिए 56 भौतिक और 56 ऑनलाइन नीलामियां लगीं। रद्द किए गए 11 ब्लॉकों में से

सात खदानों को तीसरे दौर के तहत नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया है। छह ब्लॉकों की दूसरे दौर की नीलामी तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई है।

नीलामी की तीसरी किश्त शुरू की

बयान के अनुसार, गुजरात में कुंडोल, निकल और क्रोमियम ब्लॉक पर निर्णय नामित अधिकारी द्वारा उचित समय पर लिया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी की तीसरी किश्त शुरू की। केंद्र ने अब तक 38 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी शुरू की है।

कारोबारियों को एक अप्रैल से हर हफ्ते देनी होगी गेहूं भंडार की सूचना, केंद्र सरकार का निर्देश

नई दिल्ली । केंद्र ने गेहूं की जमाखोरी व कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कारोबारियों को इसके भंडार की जानकारी हर सप्ताह सरकारी पोर्टल पर देने का आदेश दिया है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कारोबारी, थोक कारोबारी, खुदरा विक्रेता, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता व प्रोसेसर्स को एक अप्रैल से भंडार की घोषणा करनी होगी।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा, भंडार की जानकारी हर सरकारी पोर्टल पर अगले आदेश तक देनी होगी। सभी संबंधित वैधानिक संस्थाएं सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर भंडार की नियमित व उचित रूप से जानकारी प्रदान की जाए। केंद्र ने पिछले साल गेहूं के दाम नियंत्रित करने के लिए इसकी भंडारण सीमा तय की थी। यह सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही है।

देश के कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता तो कहीं छू रहा आसमान

कच्चे तेल की कीमत 83 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा

नई दिल्ली ।
वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमत 83 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर निकल गई है। क्रूड 83.12 और ब्रेंट क्रूड 86.97 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। क्रूड में यह तेजी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर असर डाल सकती है।

छत्तीसगढ़, एमपी और केरल समेत कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 0.70 पैसे तक बढ़ी हैं, जबकि गुजरात, असम, बिहार और गोवा समेत कुछ राज्यों में ईंधन 0.50 पैसे तक सस्ता हुआ है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और

डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर है, मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपये और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर है, कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपये और डीजल 90.76 रुपये प्रति लीटर है, चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये और डीजल 92.34 रुपये प्रति लीटर है। नोएडा में पेट्रोल 95.01 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर, गुरुग्राम में पेट्रोल 94.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर, चंडीगढ़ में पेट्रोल 94.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.4 रुपये प्रति लीटर, हैदराबाद में पेट्रोल 107.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.63 रुपये प्रति लीटर, जयपुर में पेट्रोल 104.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.34 रुपये प्रति लीटर, पटना में पेट्रोल 105.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.04 रुपये प्रति लीटर, लखनऊ में पेट्रोल 94.69 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.76 रुपये प्रति लीटर है।

जी एंटरटेनमेंट ने कॉस्ट कटिंग करने और ऑपरेटिंग मार्जिन के नाम पर की छंटनी

कंपनी ने टीआईसी के 50 प्रतिशत एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला

नई दिल्ली ।
जी एंटरटेनमेंट ने बेंगलुरु स्थित अपने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर के 50 प्रतिशत एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने यह छंटनी कॉस्ट कटिंग यानी लागत में कटौती और अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को बढ़ाने के लिए किया है। जी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसके बारे में जानकारी दी है।

कंपनी का कहना है कि जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड से मिली गाइडेंस के बाद टीआईसी को रिस्ट्रक्चर किया गया है। जी बोर्ड ने हाल ही में मैनेजमेंट टीम से वित्त वर्ष 2025 के लिए टीआईसी के खर्च को 600 करोड़ से 50 प्रतिशत कम करने को कहा था।

हमारा एक्सेप्शनल कंटेंट बनाने पर फोकस्ड-गोयनका

जी के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने कहा- हम एक्सेप्शनल कंटेंट

बनाने पर फोकस्ड हैं। इसे अचीव करने के लिए हमें एक क्रिएटिव एप्रोच, डिटेल्ड कंज्यूमर इनसाइड और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के मिक्सअप की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये कदम कंपनी के लिए कंटिन्यू ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए रिसोर्सेज को अनुकूलित करने और कॉस्ट इफैक्टिव स्ट्रक्चर तक पहुंचने के अप्रोच के अनुरूप हैं। टीआईसी की सुव्यवस्थित टीम अब केवल कंटेंट क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मोनेटाइजेशन की प्रोसेस में हमें सक्षम और सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

20 प्रतिशत ऑपरेटिंग मार्जिन तक पहुंचना चाहती है कंपनी

जी एंटरटेनमेंट 20 प्रतिशत ऑपरेटिंग मार्जिन तक पहुंचना चाहता है। इसके लिए बोर्ड के मैनेजमेंट ने पांच वर्टिकल - मार्गो नेटवर्क्स (शुगरबॉक्स), टेलीप्ले एंड जिदगी, हिपी, वेय्याक और लीनियर टीवी बिजनेस के इंग्लिस क्लस्टर से घाटे में कटौती करना चाहता है।

जी के देश में 50 चैनल और 40 से ज्यादा इंटरनेशनल चैनल

जी ग्लोबल कंटेंट कंपनी है, जो देश में 50 चैनल चलाती है। इसमें हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, रीजनल एंटरटेनमेंट चैनल, हिंदी मूवी चैनल और अन्य चैनल शामिल हैं। इसके साथ ही कंपनी 120 देशों में 40 से ज्यादा चैनल चलाती है। इसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जी 5 भी है। जी ने अपना पहला चैनल जी टीवी 1992 में लॉन्च किया था।

जीईएम पर चालू वित्त वर्ष में अभी तक खरीद चार लाख करोड़ रुपये के पार, सरकार ने दी जानकारी

नई दिल्ली। देश के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अधिक खरीद गतिविधियों से चालू वित्त वर्ष में अभी तक सरकारी मंच जीईएम के जरिए वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद चार लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) मंच की शुरुआत नौ अगस्त 2016 को की गई थी। जीईएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीके सिंह ने पत्रकारों से कहा, '' 28 मार्च तक खरीद चार लाख करोड़ रुपये को पार कर गई। यह ऐतिहासिक है। '' वित्त वर्ष 2021-22 में खरीद मूल्य 1.06 लाख करोड़ रुपये था और पिछले वित्त वर्ष में यह दो लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। उन्होंने कहा कि मंच से सेवाओं की खरीद वित्त वर्ष 2022-23 में 66,000 करोड़ रुपये से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में अभी तक 2.05 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इसी तरह चालू वित्त वर्ष में 28 मार्च तक मंच से 1.95 लाख करोड़ रुपये की वुस्तुएं खरीदी गईं।''वर्तमान में सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इस मंच के जरिए लेनदेन करने की अनुमति है। दुनियाभर में इस तरह के मंचों की सूची में दक्षिण कोरिया का केओएनईपीएस शीर्ष पर है।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01,-03, फैक्स नं.- 0755-2553914 e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) रजिस्टर्ड नं.म.प्र./296/भोपाल/2012-2014 आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/296/2015-2017